

उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी शिक्षा व्यवस्था में असमानता: कारण एवं समाधान

डॉ सन्तोष डबराल

प्राचार्य, ओंकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ऋषिकेश

सार

उत्तराखंड का शैक्षिक परिदृश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक विपरीतता को दर्शाता है, जो पहुँच, गुणवत्ता, बुनियादी ढाँचे और परिणामों में गहरी असमानताओं को रेखांकित करता है। यह शोध पत्र राज्य की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त असमानताओं की जाँच करता है, जहाँ शहरी केंद्रों में बेहतर सुविधाएँ, योग्य शिक्षक, डिजिटल संसाधन और पाठ्येतर अवसर उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कम धन, शिक्षकों की कमी, खराब बुनियादी ढाँचा और उच्च ड्रॉपआउट दर की समस्या है। सामाजिक-आर्थिक कारक, भौगोलिक चुनौतियाँ, प्रवास और नीति कार्यान्वयन अंतराल इस विभाजन को और बढ़ाते हैं। शोध पत्र इन असंतुलनों के पीछे प्रमुख कारणों की पहचान करता है, जिसमें ग्रामीण शिक्षा में अपर्याप्त निवेश, सामुदायिक जुड़ाव की कमी और सीमित डिजिटल पैठ शामिल हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, अध्ययन बुनियादी ढाँचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल समावेशन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अनुरूप सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है। संदर्भ-संवेदनशील नीतियों पर विशेष जोर दिया जाता है जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अनूठी स्थलाकृतिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को स्वीकार करती हैं। ग्रामीण-शहरी शैक्षिक अंतर को पाटना न केवल समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि राज्य में समावेशी विकास और सतत वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है।

मुख्य शब्द: ग्रामीण, शिक्षा व्यवस्था, समाधान, उत्तराखंड

परिचय

शिक्षा सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास की आधारशिला है। भारत में, शिक्षा का अधिकार संविधान में निहित है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सीखने के समान अवसर प्रदान करना है। हालाँकि, व्यवहार में, ग्रामीण और शहरी शिक्षा प्रणालियों के बीच महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में, जहाँ भूगोल, बुनियादी ढाँचा और सामाजिक गतिशीलता अनूठी चुनौतियाँ पैदा करती हैं। 2000 में राज्य के गठन के बाद साक्षरता दर में लगातार सुधार और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के बावजूद, उत्तराखंड एक स्पष्ट ग्रामीण-शहरी शैक्षिक विभाजन से जूझ रहा है। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्र, जैसे देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार, अच्छी तरह से स्थापित स्कूलों, प्रशिक्षित शिक्षकों तक पहुँच, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और अभिभावकों की उच्च जागरूकता से लाभान्वित होते हैं। ये शहर अक्सर शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में निवेश को आकर्षित करते हैं और निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए पसंदीदा स्थान हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्र, विशेष रूप से पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी इलाकों में, खराब सड़क संपर्क, योग्य शिक्षकों की कमी, डिजिटल बुनियादी ढाँचे की कमी और अक्सर लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने सहित गंभीर सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इस असमानता

में कई कारक योगदान करते हैं। भौगोलिक अलगाव, सीमित वित्तीय संसाधन, सामाजिक-आर्थिक नुकसान और नीति कार्यान्वयन अंतराल ने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जहां ग्रामीण छात्रों को उनके शहरी समकक्षों के समान गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की अनुपस्थिति, बहु-ग्रेड शिक्षण और जवाबदेही की कमी ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता को और खराब करती है। बेहतर शैक्षिक और आर्थिक अवसरों की तलाश में पहाड़ी गांवों से शहरी केंद्रों की ओर पलायन ने भी स्कूलों को खाली कर दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में उपेक्षा का एक दुष्चक्र शुरू हो गया है। उत्तराखंड की शिक्षा प्रणाली में सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचनात्मक कारकों के जटिल अंतर्संबंध को समझकर, अध्ययन का उद्देश्य समावेशी शैक्षिक विकास के लिए एक रोडमैप प्रदान करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह कहीं भी रहता हो, सीखने, बढ़ने और सफल होने का अवसर मिले।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा के अंतर को पाटना केवल बुनियादी ढांचे का मामला नहीं है - यह सामाजिक न्याय, समान अवसर और दीर्घकालिक विकास का मामला है। एक मजबूत शिक्षा प्रणाली गरीबी को कम कर सकती है, समुदायों को सशक्त बना सकती है और युवाओं को अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन में प्रभावी रूप से योगदान करने में सक्षम बना सकती है। उत्तराखंड में, जहाँ 65% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण शिक्षा प्रणालियों का हाशिए पर होना राज्य के समावेशी विकास लक्ष्यों के लिए एक गंभीर खतरा है। कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण शिक्षा प्रणाली की कमज़ोरियों को और उजागर किया। जहाँ शहरी छात्र अपेक्षाकृत आसानी से ऑनलाइन शिक्षा में बदलाव करने में सक्षम थे, वहीं दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण पीछे रह गए। इस डिजिटल विभाजन ने मौजूदा असमानताओं को और गहरा कर दिया, जिससे कई ग्रामीण छात्र कई महीनों की स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए, जिससे स्कूल छोड़ने का जोखिम और सीखने की हानि बढ़ गई। इस संदर्भ में, महामारी ने सभी क्षेत्रों में लचीली, न्यायसंगत और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा प्रणाली बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए एक चेतावनी के रूप में काम किया है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा की गुणवत्ता में है, न कि केवल इसकी उपलब्धता में। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में जहाँ भी स्कूल हैं, वहाँ भी शिक्षण की गुणवत्ता अक्सर पिछड़ जाती है। इसका कारण अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर विषय विशेषज्ञों की कमी और खराब छात्र-शिक्षक अनुपात है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण स्कूलों में अक्सर बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, कार्यात्मक शौचालय, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का अभाव होता है - ऐसे कारक जो सीखने के माहौल और छात्रों की संख्या को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, खासकर लड़कियों के मामले में। सांस्कृतिक और भाषाई कारक भी विभाजन में योगदान करते हैं। शहरी स्कूल अक्सर अंग्रेजी-माध्यम शिक्षा पर जोर देते हैं, जिसे बेहतर करियर संभावनाओं के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है।

इसके विपरीत, कई ग्रामीण स्कूल स्थानीय भाषाओं या हिंदी में संचालित होते रहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में ग्रामीण छात्रों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह भाषाई विभाजन संरचनात्मक असमानता का एक और रूप है जो सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालता है। इस पेपर को इस मुद्दे की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए संरचित किया गया है। बाद के खंड शैक्षिक असमानता के पीछे के कारणों का विस्तार से पता लगाएंगे - जिसमें बुनियादी ढाँचागत, आर्थिक, सामाजिक और नीति-संबंधी कारक शामिल होंगे।

इसके बाद, पेपर असमानता को कम करने के उद्देश्य से साक्ष्य-आधारित और संदर्भ-विशिष्ट समाधानों पर गहराई से चर्चा करेगा। इनमें ग्रामीण शिक्षा में निवेश बढ़ाने, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूलित डिजिटल समाधान अपनाने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाने और प्रभावी निगरानी तंत्र लागू करने जैसी नीतिगत सिफारिशें शामिल हैं। चुनौतियों और संभावित समाधानों दोनों पर प्रकाश डालते हुए, इस अध्ययन का उद्देश्य उत्तराखंड में समान शिक्षा पर चर्चा में योगदान देना और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो राज्य-स्तरीय

शिक्षा नीति को सूचित कर सकती है। लक्ष्य केवल समस्याओं की पहचान करना नहीं है, बल्कि कार्रवाई को उत्प्रेरित करना है - यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा का वादा राज्य के हर कोने तक पहुँचे, शहरी केंद्रों से लेकर सबसे दूरदराज के हिमालयी गाँवों तक।

ग्रामीण-शहरी शैक्षिक असमानताओं का राष्ट्रीय संदर्भ

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) जैसे अध्ययनों से लगातार पता चलता है कि ग्रामीण भारत में बच्चों को शहरी क्षेत्रों की तुलना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ASER (2022) के अनुसार, ग्रामीण छात्र अपने शहरी समकक्षों की तुलना में बुनियादी पढ़ने और अंकगणित कौशल में पिछड़ जाते हैं, जो लगातार सीखने की कमी को उजागर करता है। अपर्याप्त स्कूल बुनियादी ढाँचा, शिक्षकों की अनुपस्थिति और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों जैसे कारकों का अक्सर हवाला दिया जाता है। ड्रेज़ और सेन (2013) ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स में तर्क दिया है कि भारत के तेज़ आर्थिक विकास के बावजूद, ग्रामीण शिक्षा में सार्वजनिक निवेश अपर्याप्त है। वे विशेष रूप से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

पहाड़ी राज्यों और उत्तराखंड में चुनौतियाँ

उत्तराखंड के लिए विशिष्ट शोध, जैसे कि भंडारी और भट्ट (2019) द्वारा किया गया कार्य, शैक्षिक परिणामों को आकार देने में भौगोलिक अलगाव और प्रवास की भूमिका का पता लगाता है। उनके अध्ययन से संकेत मिलता है कि पहाड़ी गाँवों से शहरी केंद्रों या मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर पलायन के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कई सरकारी स्कूल कम नामांकन के कारण बंद हो गए हैं। मीडिया और सरकारी रिपोर्टों में संदर्भित ये "भूत स्कूल", ग्रामीण शिक्षा में गहरे संरचनात्मक मुद्दों का प्रतीक हैं। उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट (2018) के अनुसार, जबकि राज्य में साक्षरता दर अपेक्षाकृत अधिक (79.6%) है, ग्रामीण और शहरी जिलों के बीच महत्वपूर्ण असमानता है। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में बताया गया है कि देहरादून और नैनीताल जैसे जिले बागेश्वर या चंपावत जैसे पहाड़ी जिलों की तुलना में शैक्षिक संकेतकों में बहुत बेहतर हैं। रिपोर्ट लैंगिक असमानताओं की ओर भी इशारा करती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहाँ लड़कियों के घरेलू जिम्मेदारियों, सुरक्षित परिवहन की कमी या कम उम्र में शादी के कारण स्कूल छोड़ने की संभावना अधिक होती है।

डिजिटल डिवाइड और कोविड के बाद का युग

कोविड-19 महामारी ने शिक्षा में डिजिटल डिवाइड की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। उत्तराखंड में, जहाँ कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्मार्टफ़ोन की कमी है, ऑनलाइन शिक्षा केवल शहरी छात्रों के लिए उपलब्ध एक विशेषाधिकार बन गई है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में जैन और राजन (2021) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इस डिजिटल बहिष्कार ने सीखने के अंतराल को कैसे चौड़ा किया है। यूनेस्को (2021) की "कोविड-19 के समय में शिक्षा" पर एक रिपोर्ट ने स्कूल बंद होने के असमान प्रभाव पर जोर दिया, खासकर दूरदराज और अविकसित क्षेत्रों में। उत्तराखंड में, इसका मतलब ग्रामीण छात्रों के लिए लंबे समय तक शैक्षिक व्यवधान रहा और पहले से मौजूद असमानताएँ और गहरी हो गईं।

नीतिगत ढाँचे और सरकारी पहल

भारत सरकार ने ग्रामीण शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से कई नीतियाँ शुरू की हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और समग्र शिक्षा अभियान। हालाँकि इन कार्यक्रमों से नामांकन और प्रतिधारण में सुधार हुआ है, लेकिन उत्तराखंड के दूरदराज के इलाकों में सीखने के परिणामों और शैक्षिक गुणवत्ता पर इनका प्रभाव सीमित रहा है। कुमार और पाठक (2020) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ग्रामीण उत्तराखंड में इन नीतियों की सफलता अक्सर खराब क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार और सामुदायिक भागीदारी की कमी के कारण बाधित होती है। वे शिक्षा प्रशासन के विकेंद्रीकरण, स्थानीय समुदायों और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को शिक्षा वितरण की देखरेख करने के लिए सशक्त बनाने की वकालत करते हैं।

शिक्षकों और समुदाय की भूमिका

भारत में ग्रामीण शिक्षा पर साहित्य में शिक्षक-संबंधी चुनौतियों पर अक्सर चर्चा की जाती है। गोविंदा और वर्गीस (2023) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण विद्यालयों में बहु-ग्रेड शिक्षण, खराब शिक्षक प्रेरणा और निरंतर व्यावसायिक विकास की अनुपस्थिति अधिक प्रचलित है। उत्तराखंड में, दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को अक्सर आवागमन, आवास की कमी और शिक्षण सहायक सामग्री तक सीमित पहुँच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए समुदाय की भागीदारी को भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना जाता है। ग्रामीण भारत में एक यादृच्छिक मूल्यांकन में बनर्जी एट अल. (2010) ने पाया कि माता-पिता की जागरूकता और सामुदायिक निगरानी में वृद्धि से सीखने के परिणामों में काफी सुधार हुआ है। जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

वैश्विक स्तर पर, ग्रामीण-शहरी शैक्षिक असमानता केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (2020) बताती है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में ग्रामीण समुदाय किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रमुख सिफारिशों में स्थानीय पाठ्यक्रम विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश, तथा ऑफ-ग्रेड क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चालित डिजिटल उपकरणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना शामिल है - ये ऐसे सबक हैं जिन्हें उत्तराखंड के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

उद्देश्य

1. उत्तराखंड में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक असमानताओं में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों की पहचान और विश्लेषण करना, जिसमें अवसंरचनात्मक, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक और डिजिटल आयाम शामिल हैं।
2. उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक और संदर्भ-विशिष्ट समाधान प्रस्तावित करना।
3. उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन का अध्ययन करना।
4. उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र के विकास का अध्ययन करना।

शोध पद्धति:

इस शोध पत्र में प्रयुक्त शोध पद्धति अनुप्रयुक्त और मात्रात्मक प्रकृति की है। अनुप्रयुक्त शोध, व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने के तरीकों की जांच है। इस शोध का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के विकास और वर्तमान चरण पर चर्चा करना है। तथा शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान खोजना है। वर्तमान अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए डेटा विश्लेषण के लिए द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया।

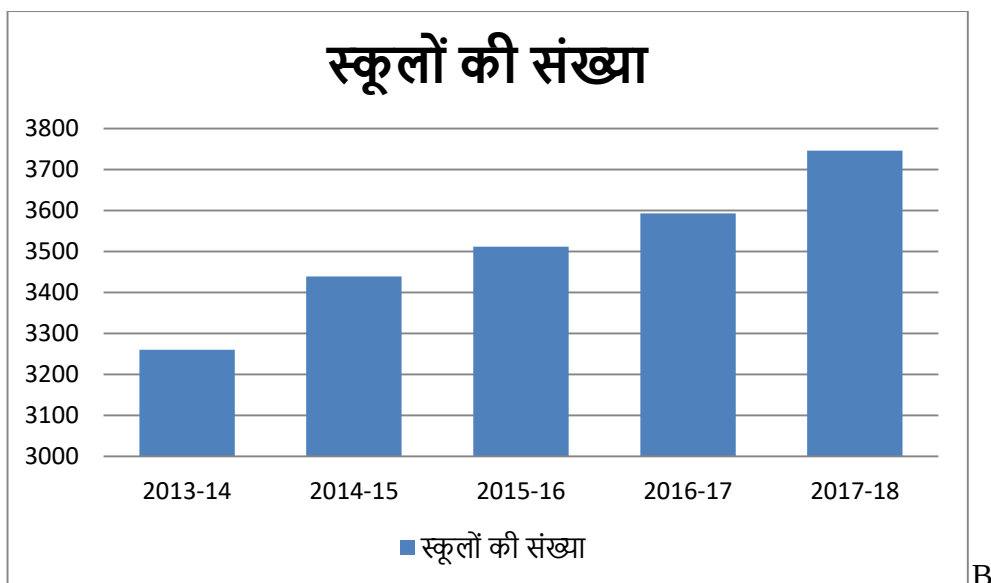
डेटा विश्लेषण और व्याख्या

यूडीआईएसई रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि 2013-14 के दौरान उत्तराखंड में स्कूलों की संख्या 3260 थी जो 2014-15 में बढ़कर 3439 हो गई। 2015-16 में स्कूलों की संख्या 3512 थी और 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः 3593 और 3746 थी। इस प्रकार, यह दर्शाता है कि स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन धीमी गति से।

तालिका 1.

वर्ष	स्कूलों की संख्या
2013-14	3260
2014-15	3439
2015-16	3512
2016-17	3593
2017-18	3746

हालांकि रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से माध्यमिक स्तर पर छात्रों का नामांकन लगातार घट रहा है। निम्नलिखित आंकड़ा 1 दर्शाता है कि छात्रों के नामांकन में गिरावट का रुझान रहा है। वर्ष 2013-14 में माध्यमिक स्तर पर नामांकित कुल छात्रों की संख्या 209834 थी जो 2014-15 में घटकर 205766 हो गई। वर्ष 2015-16 में छात्रों का नामांकन घटता रहा और 198188 रहा, जो वर्ष 2016-17 में घटकर 185292 हो गया। 2017-18 में गिरावट के रुझान के साथ नामांकन 180132 रहा।



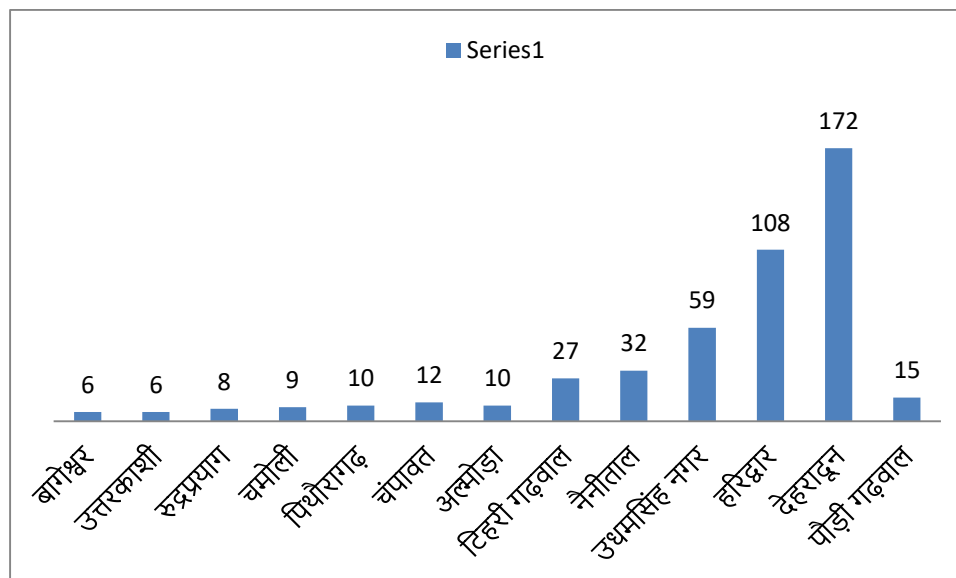
चित्र 1.

यूडीआईएसई की प्रकाशित रिपोर्टों के एक अन्य डेटा से पता चलता है कि अभी भी सैकड़ों स्कूल उचित बुनियादी ढांचे के बिना हैं। 826 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं थे जबकि 849 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं थे। 810 स्कूलों में पीने के पानी की उचित सुविधा नहीं थी और 8615 स्कूलों में छात्रों के लिए खेल का मैदान नहीं था, जो एक बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। 6000 से अधिक स्कूलों में रैंप नहीं थे और 1597 स्कूल उचित पुस्तकालय के बिना चल रहे थे। कुछ क्षेत्रों में स्कूल में नामांकन में गिरावट चिंताजनक स्थिति में है। श्री रवींद्र बर्थवाल द्वारा दैनिक जागरण में प्रकाशित एक लेख से पता चलता है कि उत्तराखंड में 2044 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों का नामांकन 10 से कम है और इसलिए सरकार द्वारा उन्हें बंद कर दिया जाएगा। यह उत्तराखंड के कुल स्कूलों का 13 प्रतिशत है। 60 से अधिक सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें शून्य नामांकन है। पौड़ी में 380, पिथौरागढ़ में 330, अल्मोड़ा में 280, टिहरी में 170, चमोली में 165, देहरादून में 122, उत्तरकाशी में 105, रुद्रप्रयाग में 90, बागेश्वर में 75, चंपावत में 60, नैनीताल में 45 और ऊधमसिंह नगर में 04 प्राथमिक स्कूल हैं, जहां छात्रों की संख्या 10 से कम है। नामांकन के इस स्तर का एक महत्वपूर्ण कारक पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों द्वारा बड़ी संख्या में पलायन है। कुछ अन्य कारक उचित बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की उपलब्धता, निजी स्कूलों से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। उच्च संस्थानों में नामांकन दर भी संतोषजनक नहीं है। एआईएसएचई रिपोर्ट (2016-17) के अनुसार उच्च शिक्षा में नामांकित कुल छात्रों की संख्या 380654 है। निम्नलिखित

तालिका 2. उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में संस्थानों की संख्या के साथ-साथ छात्रों के नामांकन को दर्शाती है।

क्रम संख्या	जिला	संस्थानों की संख्या	नामांकित छात्रों की संख्या
1	बागेश्वर	6	4,613
2	उत्तरकाशी	6	8,394
3	रुद्रप्रयाग	8	3,599
4	चमोली	9	9,911
5	पिथौरागढ़	10	13,336

6	चंपावत	12	4,464
7	अल्मोड़ा	10	11,800
8	टिहरी गढ़वाल	27	6,955
9	नैनीताल	32	52,657
10	उधमसिंह नगर	59	40,588
11	हरिद्वार	108	60,195
12	देहरादून	172	1,28,663
13	पौड़ी गढ़वाल	15	11,200



चित्र : 2 उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में संस्थानों की संख्या के साथ-साथ छात्रों के नामांकन को दर्शाती है।

उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा का परिदृश्य भौगोलिक और जनसांख्यिक विविधताओं के आधार पर असमानता दर्शाता है। राज्य के 13 जिलों में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और उनमें नामांकित छात्रों की संख्या को देखने से यह स्पष्ट होता है कि शहरी और तराई क्षेत्रों में जहां संस्थानों की अधिकता है, वहीं पर्वतीय जिलों में यह संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। सबसे अधिक संस्थान देहरादून जिले में स्थित हैं, जिनकी संख्या 172 है और यहाँ छात्रों की संख्या भी सर्वाधिक, अर्थात् 1,28,663 है। यह जिले की राजधानी होने, संसाधनों की प्रचुरता, शैक्षिक वातावरण, और विभिन्न निजी व सरकारी विश्वविद्यालयों की उपस्थिति के कारण संभव हुआ है। देहरादून में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि दून यूनिवर्सिटी, ग्राफिक एरा, उत्तरांचल विश्वविद्यालय आदि ने इसे राज्य का शैक्षिक केंद्र बना दिया है। दूसरे स्थान पर हरिद्वार जिला आता है, जहाँ 108 उच्च शिक्षा संस्थान और 60,195 छात्र हैं। यह जिला भी अपेक्षाकृत समृद्ध, तराई क्षेत्र में स्थित है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया तथा IIT रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की उपस्थिति ने उच्च शिक्षा के विकास को गति दी है।

इसके बाद उधमसिंह नगर (59 संस्थान, 40,588 छात्र) और नैनीताल (32 संस्थान, 52,657 छात्र) का स्थान आता है। इन जिलों में भी संसाधनों की उपलब्धता, बेहतर कनेक्टिविटी और उच्च शैक्षिक मांग ने शिक्षा संस्थानों को आकर्षित किया है। इसके विपरीत, पर्वतीय जिलों जैसे बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग,

और उत्तरकाशी में संस्थानों की संख्या 6 से 12 के बीच है और नामांकित छात्रों की संख्या 3,000 से 8,000 के मध्य सीमित है। यह भौगोलिक विषमता, कठिन आवागमन, सीमित शहरीकरण और आर्थिक संसाधनों की कमी का परिचायक है। इन जिलों के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अक्सर अन्य जिलों या राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है।

पिथौरागढ़ और चमोली जैसे जिलों में छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक (13,336 और 9,911 क्रमशः) है, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति रुचि और अवसरों में विस्तार हुआ है। विशेष रूप से अल्मोड़ा जिले में 10 संस्थानों में लगभग 11,800 छात्र नामांकित हैं, जो दर्शाता है कि यहां शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अच्छा विकास हुआ है। टिहरी गढ़वाल जिले में 27 संस्थान हैं, परंतु छात्रों की संख्या मात्र 6,955 है। यह अंतर इंगित करता है कि संस्थानों की उपस्थिति मात्र से शिक्षा का व्यापक प्रसार संभव नहीं है। यदि संस्थान गुणवत्ता, संसाधन, शिक्षकों की उपलब्धता और कोर्स की विविधता प्रदान नहीं करते हैं, तो छात्र वहाँ प्रवेश लेने में रुचि नहीं दिखाते। पौड़ी गढ़वाल का अनुमानित आंकड़ा (15 संस्थान और 11,200 छात्र) इसे मध्यवर्ती स्थिति में रखता है। यह जिला ऐतिहासिक रूप से शैक्षिक दृष्टि से समृद्ध रहा है, जहाँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ शिक्षा को लेकर जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक है। इस समूचे विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा का वितरण असमान है। तराई और शहरी क्षेत्रों में जहाँ संस्थानों और छात्रों की सघनता है, वहीं दूरदराज के पर्वतीय जिलों में शिक्षा की पहुंच सीमित है। यह स्थिति राज्य सरकार के लिए नीतिगत चुनौती प्रस्तुत करती है। यदि समग्र विकास सुनिश्चित करना है तो पर्वतीय जिलों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे, डिजिटल संसाधनों, छात्रावास सुविधाओं, परिवहन और शिक्षक उपलब्धता को प्राथमिकता देनी होगी।

इसके अलावा, निजी क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, ताकि वे वहाँ गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना करें। इसके लिए कर प्रोत्साहन, अनुदान और लॉजिस्टिक सहयोग जैसे उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच भी पर्वतीय युवाओं तक पहुँचाई जानी चाहिए, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। अंततः, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार "एकीकृत उच्च शिक्षा नीति" बनाए, जो क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हुए सभी जिलों में समान शिक्षा अवसर उपलब्ध कराए। इससे न केवल शिक्षा का प्रसार होगा, बल्कि युवाओं का पलायन भी रुकेगा और स्थानीय विकास को गति मिलेगी।

निष्कर्ष

उत्तराखंड में ग्रामीण और शहरी शिक्षा प्रणालियों के बीच लगातार असमानता गहरी संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों को दर्शाती है जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। विभिन्न सरकारी पहलों और साक्षरता और स्कूल नामांकन में क्रमिक सुधारों के बावजूद, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बुनियादी ढाँचे, डिजिटल उपकरणों और सीखने के परिणामों तक पहुँच के मामले में अपने शहरी समकक्षों से काफी पीछे हैं। भौगोलिक बाधाओं, आर्थिक विषमताओं, प्रवास के रुझान और शैक्षिक नीतियों के असंगत कार्यान्वयन से यह विभाजन और भी बढ़ गया है। देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरी केंद्र बेहतर संसाधनों, निजी संस्थानों, अनुभवी संकाय और तकनीकी सहायता तक पहुँच के साथ शैक्षिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। दूसरी ओर, ग्रामीण और पहाड़ी जिले कम संसाधन वाले स्कूलों, खराब प्रशिक्षित या अनुपस्थित शिक्षकों, सीमित पाठ्येतर अवसरों और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी से पीड़ित हैं। ये नुकसान न केवल शैक्षणिक विकास में बाधा डालते हैं बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को भी सीमित करते हैं, जिससे गरीबी और अविकसितता का चक्र चलता रहता है। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा में महत्वपूर्ण डिजिटल विभाजन को उजागर करके पहले से मौजूद असमानताओं को उजागर और गहरा कर

दिया है। शहरी क्षेत्रों में छात्रों ने अपेक्षाकृत आसानी से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की, जबकि ग्रामीण छात्र अक्सर इंटरनेट एक्सेस, स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बाहर रह गए। इस अवधि के दौरान सीखने की क्षमता में कमी का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है, खासकर हाशिए के समुदायों के छात्रों पर। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक, समावेशी और संदर्भ-संवेदनशील रणनीति आवश्यक है। दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही ग्रामीण स्कूलों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने चाहिए। कम लागत वाले और सुलभ शिक्षण उपकरणों सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण छात्र तेजी से डिजिटल होती दुनिया में पीछे न छूट जाएं। निष्कर्ष रूप में, उत्तराखंड में ग्रामीण-शहरी शैक्षिक विभाजन को पाटना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। शिक्षा को हर बच्चे के लिए समान रूप से सुलभ, आकर्षक और सशक्त बनाया जाना चाहिए, चाहे वे कहीं भी रहते हों। नीति सुधार, तकनीकी नवाचार, सामुदायिक भागीदारी और निरंतर निवेश को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर, उत्तराखंड एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ सकता है - जो समाज के सभी वर्गों का उत्थान करती है और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करती है।

संदर्भ

- [1] ASER सेंटर. (2022)। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2022। <http://www.asercentre.org> से लिया गया
- [2] बनर्जी, ए., बनर्जी, आर., डुप्लो, ई., ग्लेनरस्टर, आर., और खेमानी, एस. (2010)। सहभागी कार्यक्रमों के नुकसान: भारत में शिक्षा में यादृच्छिक मूल्यांकन से साक्ष्य। अमेरिकन इकोनॉमिक जर्नल: इकोनॉमिक पॉलिसी, 2(1), 1-30।
- [3] भंडारी, एस., और भट्ट, बी.पी. (2019)। पहाड़ी क्षेत्रों में शैक्षिक विकास: उत्तराखंड में चुनौतियाँ और अवसर। इंडियन जर्नल ऑफ हिल एजुकेशन, 5(1), 45-53।
- [4] ड्रेज़, जे., और सेन, ए. (2013)। एक अनिश्चित गौरव: भारत और इसके विरोधाभास। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
- [5] गोविंदा, आर., और वर्गीस, एन.वी. (2023)। भारत में प्राथमिक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता: मध्य प्रदेश का एक केस स्टडी। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (IIEP), यूनेस्को।
- [6] जैन, एम., और राजन, एस. (2021)। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल डिवाइड और शिक्षा। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 56(6), 23-26।
- [7] कुमार, एस., और पाठक, आर. (2020)। भारत में ग्रामीण शिक्षा की चुनौतियाँ: उत्तराखंड का एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज रिव्यू, 8(3), 45-52।
- [8] शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। (2018)। समग्र शिक्षा अभियान: स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना। <https://www.education.gov.in> से लिया गया।

- [9] एनएसएसओ। (2019)। भारत में शिक्षा पर घरेलू सामाजिक उपभोग: एनएसएस 75वां दौर (2017-18)। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।
- [10] यूनेस्को। (2020)। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020: समावेश और शिक्षा - सब कुछ मतलब सब कुछ। पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन।
- [11] यूनेस्को। (2021)। कोविड के बाद की दुनिया में शिक्षा: सार्वजनिक कार्रवाई के लिए नौ विचार। पेरिस: यूनेस्को भविष्य की शिक्षा पहल।
- [12] उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट। (2018)। भारत सरकार के योजना आयोग के सहयोग से उत्तराखंड सरकार। <http://www.planning.uk.gov.in> से लिया गया
- [13] . चौहान, ए और सती, ए (2016)। उत्तराखंड, भारत में शिक्षा के अधिकार की संभावनाएँ, चुनौतियाँ और उपलब्धियाँ। शिक्षा विज्ञान की शोध पत्रिका, 4(5):1-4।
- [14] पांडे, एच (2017-2018)। उत्तराखंड में प्रवास और उच्च शिक्षा (सरकारी कॉलेजों के लिए विशेष संदर्भ)। पुणे रिसर्च डिस्कवरी-अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन पत्रिका, 2(4):1-13।
- [15] पांडे, टी.डी और पाठक, जे (2018)। उच्च शिक्षा और सतत विकास। रिसर्च रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, 3(3):79-83.
- [16] यू-डीआईएसई रिपोर्ट। डीआईएसई रिपोर्ट से लिया गया: <http://rmsa.uk.gov.in>.
- [17] रुहेला, आर (2017)। उत्तराखंड क्षेत्र में प्राथमिक छात्रों के ड्रॉपआउट स्तर का अध्ययन। अंतःविषय अध्ययन के लिए स्कॉलरली रिसर्च जर्नल, 4(31):5439-5445।